नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 02
दि. 02.10.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

खबर संक्षेप

सिद्धरमैया ने पांच साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का जताया विश्वास

मैसुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को स्पष्ट किया कि वह पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। यह बयान उस समय आया जब कुछ कांग्रेस नेताओं, जिनमें कुणिगल विधायक एच.डी. रंगनाथ भी शामिल हैं, ने कहा था कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।

सिद्धरमैया ने संवाददाताओं से कहा, ₹मैं पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहूंगा।₹ उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि वह अगले साल मैसुरु के शाही दशहरा समारोह के दौरान पारंपरिक पुष्पार्चन करेंगे। यह परंपरा हर साल मुख्यमंत्री द्वारा दशहरा के अवसर पर की जाती है।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह पार्टी आलाकमान के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा, उन्हें उसका पालन करना होगा। इस बयान से स्पष्ट हुआ कि सिद्धरमैया अपने पद को लेकर स्थिर और प्रतिबद्ध हैं और कांग्रेस पार्टी की लाइन के अनुसार काम करने को तैयार हैं।

दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले का लाभ 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीए और डीआर में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया (एरियर्स) अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलेगा।

सरकार ने इस बढ़ोतरी के लिए 10,084 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस वृद्धि के बाद कुल महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। मार्च 2025 में महंगाई भत्ते में केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले सात साल में सबसे कम थी। आमतौर पर यह बढ़ोतरी 3 से 4 प्रतिशत के बीच होती है, लेकिन इस बार दिवाली से पहले इसे पूरा किया गया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते के अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सरकार ने 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया, जो पिछले साल 2,425 रुपए था। फसल वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का उत्पादन लक्ष्य 11.9 करोड़ टन रखा गया। इसके साथ ही दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना भी मंजूर की गई। पीएम आशा गारंटी योजना के तहत MSP दालों की सरकारी खरीद सीमा 45,000 करोड़ से बढ़ाकर 60,000 करोड़ की गई। शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया। कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी। इनमें से 7 विद्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होंगे, जबकि 50 को राज्य सरकार संभालेगी। 20 ऐसे स्कूल भी खोले जाएंगे जहां पहले केंद्रीय विद्यालय नहीं थे। वहीं, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नेशनल हाईवे-715 के कालियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को फोर-लेन बनाने की मंजूरी दी गई, जिसकी लंबाई 86 किलोमीटर और लागत 6,967 करोड़ रुपये है। इस हाईवे से तेजपुर और झांजी के बीच संपर्क मजबूत होगा। इसके अलावा बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई, जिस पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस कार्यक्रम के तहत 401 रिसर्चर्स को छह साल तक समर्थन मिलेगा, जिसमें 192 रिसर्च फेलोशिप, 106 अनुदान और 103 रिसर्च मैनेजमेंट शामिल हैं।

इस तरह केंद्र सरकार ने न केवल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली से पहले आर्थिक राहत दी है, बल्कि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में भी ऐसे बड़े फैसले किए हैं, जो आने वाले समय में देश के व्यापक विकास और सुधार में मददगार साबित होंगे।

मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारियों का दबदबा, कलेक्टर पदों पर बढ़ी नियुक्तियां

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में अब अधिकांश कलेक्टर पद सीधे भर्ती हुए आईएएस अधिकारियों के हाथों में हैं, जबकि पहले यह संतुलन राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट अधिकारियों और सीधी भर्ती अधिकारियों के बीच लगभग बराबर था। 55 जिलों में से केवल 14 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में कलेक्टर अब सीधी भर्ती के अधिकारी हैं। इस बदलाव से स्पष्ट हो गया है कि अब सीधी भर्ती अधिकारियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। वहीं, कुछ प्रमोटी अधिकारी जैसे नियाज खान, उर्मिला शुक्ला, गिरीश शर्मा और सरिता बाला प्रजापति अभी भी कलेक्टर पद पर नहीं आ सके हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्षों में आईएएस संवर्ग में प्रमोट अधिकारियों की संख्या कम रही, इसलिए विभिन्न बैच के अधिकारियों के बीच संतुलन बनाकर कलेक्टर नियुक्त किए गए। 2016 बैच के सभी सीधी भर्ती अधिकारियों को कलेक्टर बनाया जा चुका है, लेकिन इसी बैच के 16 प्रमोटी अधिकारी अब भी पदस्थापना का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कई अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके या सेवानिवृत्ति के करीब हैं, लेकिन उन्हें कभी कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं मिली।

कलेक्टर पदों पर एससी-एसटी वर्ग के अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। वर्तमान में 17 कलेक्टर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। मंगलवार को सात महिला अधिकारियों को कलेक्टर बनाया गया, जिससे प्रदेश में कुल महिला कलेक्टरों की संख्या 17 हो गई है।

पूर्व मुख्य सचिव शरद चंद्र बेहार ने कहा कि आमतौर पर कलेक्टर की नियुक्ति में अनुभव और योग्यता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन अब नियुक्तियों में राजनीतिक पसंद-नापसंद भी अधिक प्रभाव डाल रही है। मध्य प्रदेश ही नहीं, अधिकतर राज्यों में प्रमोटी और सीधी भर्ती अधिकारियों के बीच संतुलन नहीं रखा जा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नियुक्तियों में केवल बैच नहीं बल्कि योग्यता और उपयोगिता पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस बदलाव से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश प्रशासन में अब सीधी भर्ती आईएएस अधिकारियों का दबदबा बढ़ गया है और कलेक्टर पदों पर उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

योगी राज में यूपी बना 'जीरो दंगा' वाला राज्य, अपराध दर में भी बड़ी गिरावट

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में राज्य ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 'क्राइम इन इंडिया 2023' रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यूपी में सांप्रदायिक और धार्मिक दंगों की संख्या शून्य रही। यह राज्य के लिए एक नई मिसाल है, क्योंकि प्रदेश में इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि यूपी में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 25 प्रतिशत कम रही, जो कि 335.3 दर्ज की गई, जबकि पूरे देश में औसत अपराध दर 448.3 थी। यह आंकड़ा न केवल योगी सरकार की सख्त कानून-व्यवस्था नीति का प्रतीक है, बल्कि बड़े जनसंख्या वाले राज्य में कानून और व्यवस्था को मजबूती से लागू करने का उदाहरण भी है।

एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 से 2017 के बीच यूपी में कुल 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें 192 लोगों की जान गई। इसके पहले, 2007 से 2011 के बीच 616 घटनाओं में 121 लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में पिछली सरकारों के समय हिंसा और दंगों की घटनाओं में कितनी वृद्धि थी। लेकिन 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई और उसकी लगातार कड़ी कार्रवाई से प्रदेश में अब तक कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। बरेली और बहराइच में दो छोटी हिंसक घटनाएं हुईं, लेकिन सरकार ने 24 घंटे के भीतर नियंत्रण कायम कर दिया, जिससे यह दिखा कि त्वरित और प्रभावी कदमों से हिंसा को रोका जा सकता है।

सिर्फ दंगों पर अंकुश नहीं लगाया गया, बल्कि यूपी में अपराध की अन्य श्रेणियों में भी राष्ट्रीय औसत से कमी दर्ज की गई। बलवा के मामलों में पूरे देश में 39,260 मामले दर्ज हुए, जबकि यूपी में केवल 3,160 मामले आए। इसी तरह, फिरौती के लिए अपहरण के मामले देश में 615 दर्ज हुए, जबकि यूपी में केवल 16 मामले सामने आए। डकैती (IPC 395) के मामलों में देश में 3,792 मामले थे, जबकि यूपी में मात्र 73 मामले दर्ज हुए, जो इसे 'नियर जीरो' क्राइम रेट वाले राज्यों की श्रेणी में लाता है। बड़ी जनसंख्या और घनी बस्तियों वाले राज्य में यह अभूतपूर्व उपलब्धि योगी सरकार की सख्त नीतियों और त्वरित कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी शासन व्यवस्था, कानून का सख्त पालन और त्वरित कार्रवाई ने प्रदेश में शांति और सुरक्षा की ऐसी स्थिति पैदा की है, जिसे पूरे देश में सराहा जा रहा है। योगी सरकार ने केवल पुलिस बल बढ़ाने या कानून-व्यवस्था को कागजों तक सीमित रखने तक संतोष नहीं किया, बल्कि प्रशासनिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर सक्रिय कदम उठाए। सामुदायिक स्तर पर जन संवाद, विवादों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई और हिंसा में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई से प्रदेश में नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा मिला।

यूपी में यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए गर्व का विषय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का भी स्रोत है। यह साबित करता है कि बड़े जनसंख्या वाले और विविध सांस्कृतिक परिवेश वाले राज्य में भी सख्त प्रशासन, त्वरित न्याय और सामुदायिक भागीदारी के जरिए अपराध और दंगों को नियंत्रित किया जा सकता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योगी सरकार का यह मॉडल सिर्फ कानून-व्यवस्था की सफलता नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और शांति कायम करने का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

यूपी में शांति और सुरक्षा के इस संकल्प ने यह संदेश दिया है कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, अगर प्रशासन, पुलिस, समाज और सरकार मिलकर काम करें तो हिंसा और अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। भविष्य में इस नीति को निरंतर बनाए रखना और नए तरीकों से मजबूत करना राज्य की शांति और विकास के लिए आवश्यक है। योगी राज में यह उपलब्धि प्रदेश के नागरिकों के जीवन में विश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है और इसे अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है।

भाजपा सांसद बृज लाल बने लोक शिकायत-न्याय समिति के अध्यक्ष, संसदीय समितियों का गठन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। लोकसभा में चयनित समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। इसमें भाजपा सांसद बृज लाल को कर्मी, लोक शिकायत, कानून और न्याय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से शामिल हैं। समिति का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में सुधार करना और जन शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

साथ ही, भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा को इन्सॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी कोड (संशोधन) बिल 2025 की चयनित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पांडा की अध्यक्षता में गठित इस समिति में कुल 24 सदस्य शामिल होंगे, जो लोकसभा और राज्यसभा से हैं। समिति का मुख्य कार्य इन्सॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी कोड (संशोधन) बिल 2025 पर विचार करना और आवश्यक सिफारिशें देना है।

सांसद पांडा पहले भी आर्थिक और विधायी मामलों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं और उनके नेतृत्व में समिति से कानून को और अधिक प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। बृज लाल की अध्यक्षता वाली समिति से जन शिकायतों के निवारण और न्यायिक सुधारों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की संभावना है।

आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बरकरार रखा, लोन महंगे नहीं होंगे

(जीएनएस)। मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लगातार दूसरी बार अपनी रेपो रेट 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि बैंकों से लिए जाने वाले लोन महंगे नहीं होंगे और आपके ईएमआई में कोई बदलाव नहीं आएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 1 अक्टूबर को इस निर्णय की जानकारी दी।

यह फैसला 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में लिया गया। गवर्नर ने बताया कि MPC के सभी सदस्य ब्याज दरों को स्थिर रखने के पक्ष में थे। जीएसटी में कटौती और महंगाई में कमी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया।

आरबीआई का रेपो रेट वह दर है जिस पर वह बैंकों को लोन देता है। इसमें कोई बदलाव न होने का अर्थ है कि ब्याज दरें न तो बढ़ेंगी और न घटेंगी।

इस साल आरबीआई ने तीन बार रेपो रेट में कटौती की है। फरवरी में इसे 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया, अप्रैल में 0.25% की कटौती हुई और जून में 0.50% की कटौती की गई। कुल मिलाकर इस साल ब्याज दरों में 1% की कमी हुई है। साथ ही, इस बैठक में देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया गया। यह संकेत है कि आर्थिक स्थिति में सुधार और विकास की संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। इस निर्णय से उपभोक्ताओं और उधारकर्ताओं दोनों को स्पष्ट संदेश गया है कि इस समय लोन की लागत स्थिर रहेगी और मौद्रिक नीति में सावधानी बरती जा रही है ताकि आर्थिक विकास और महंगाई दोनों पर संतुलन बना रहे।

संपादकीय

कनाडा की पहल भारतीय चिंताओं के अनुरूप

भारत और विदेशों में भय और असुरक्षा का माहौल बनाने वाले बिश्नोई गिरोह को कनाडा द्वारा आतंकवादी संगठन की सूची में डालने के कारण समझना कठिन नहीं है। यह कदम इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के बारे में भारत की चिंताओं को सही साबित करने वाला ही है। वहीं दूसरी ओर यह गैंगस्टर व आतंकवादी गठजोड़ पर कार्रवाई करने का एक स्वागत योग्य प्रयास भी है। जिसने दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सतर्क भी किया है। दरअसल, यह गिरोह लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में भय व आतंक का पर्याय बना हुआ है। जिसने अनेक हाई-प्रोफाइल अपराधों को समय-समय पर अंजाम दिया है। यह विडंबना है और तंत्र की विफलता भी है कि गैंग का मुखिया पिछले एक दशक से अधिक समय से जेल में बंद है, इसके बावजूद गंभीर अपराधों की योजना बनाता रहा है। बिश्नोई गिरोह पर हाल के वर्षों में कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं को अंजाम देने का आरोप है। इन हाई-प्रोफाइल हत्याओं में प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दिकी भी शामिल हैं। अपराधियों के गठबंधन ने बार-बार बॉलीवुड स्टार सलमान खान को हत्या की धमकी दी है। इस सिंडिकेट ने सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर भी हमले करवाए हैं। इसी तरह कनाडा में पंजाबी कलाकार ए.पी. ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल के घरों के बाहर गोलाबारी में भी इस गिरोह की भूमिका बतायी गई है। दरअसल, भारत सरकार व कनाडा सरकार ने इस आपराधिक सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई के लिये इसलिए भी सहयोग बढ़ाया है क्योंकि बिश्नोई गिरोह पर कनाडा में सक्रिय गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर जबरन वसूली का कारोबार चलाने का आरोप बराबर लगता रहा है। बताया जाता है कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से करीबी संबंध रहे हैं। जो दोनों देशों की कानून व्यवस्था के लिये एक बड़ी चुनौती बना रहा है।

हाल के दिनों में खबरें आती रही हैं कि बिश्नोई गैंग अपने भीतरी टकराव से जूझ रहा है। गिरोह में लगातार जारी आपसी झड़पों और विश्वासघात की निरंतर बढ़ती घटनाओं ने बिश्नोई गैंग को भीतर से भी कमजोर कर दिया है। इस स्थिति को भारत तथा कनाडा की सरकारों की कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों ने इन कुख्यात अपराधियों पर चारों ओर से शिकंजा कसने के अवसर के रूप में देखा है। दरअसल, कनाडा सरकार के द्वारा बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल करने के बाद अधिकारियों को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में सुविधा रहेगी। वहां के कानून के अनुसार बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद अब कनाडाई अधिकारियों को आतंकवादी मामलों में इन अपराधियों के खिलाफ अपराध साबित करने के लिये अतिरिक्त साधन व सुविधा मिल सकेगी। सरल शब्दों में कहें तो आतंकवादी संगठन घोषित करने के बाद कनाडाई अधिकारियों को बिश्नोई गिरोह की संपत्ति, वाहन और धन जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। इसमें वित्त पोषण से संबंधित मामलों में की जाने वाली कार्रवाई भी शामिल है। जिसके जरिये भारत में अपराध व हिंसा फैलाने की साजिश रची जाती रही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक सुरक्षा कनाडा सरकार की प्राथमिकता रही है। जो यह भी दर्शाता है कि कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए कुख्यात गैंगस्टरों, आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा उत्पन्न गंभीर खतरे को पहचाना है। निस्संदेह, देर-सवेर इस ज़ीरो टॉलरेंस की नीति से भारत को अपने आंतरिक सुरक्षा प्रयासों को भी मजबूती देने में मदद मिलेगी। भारत लंबे समय से कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाले अलगाववादी संगठनों व व्यक्तियों के खिलाफ शिकंजा कसने की मांग करता रहा है। बिश्नोई गैंग के खिलाफ ताजा कार्रवाई से अब उम्मीद जगी है कि देर-सवेर कनाडा सरकार भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए इन संगठनों पर कार्रवाई करेगी, जो भारत के खिलाफ लगातार विषवमन करते रहे हैं और भारत विरोधी अभियानों का वित्तीय पोषण करते रहे हैं।

गांधी और गांधी विचार को कुचलने की कुचेष्टाएं कब तक?

> गांधी महज एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दर्शन हैं। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत विश्व राजनीति, समाज और मानवता के लिए अब भी सबसे बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। इसीलिए हिंसक मानसिकताएं बार-बार इन मूल्यों को मूक बनाने या कुचलने का प्रयास करती हैं।

लंदन के प्रसिद्ध टैविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की 57 साल पुरानी कांस्य की प्रतिमा पर हुआ हमला केवल एक मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की घटना भर नहीं है, बल्कि यह गांधी के अस्तित्व, उनके विचार और भारत की आत्मा पर आघात है। गांधी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करते हुए काले रंग से लिखा है, 'गांधी- मोदी, हिंदुस्तानी टेररिस्ट...।' वहां एक तिरंगे का भी अपमान किया गया है और उसपर भी 'टेररिस्ट' लिखा हुआ है। जिस समय यह हमला हुआ, वह भी बेहद प्रतीकात्मक है, अंतरराष्ट्रीय गांधी जयंती यानी अहिंसा दिवस से महज तीन दिन पहले। यह समय का ऐसा चयन है जो यह दर्शाता है कि अहिंसा के विचार और गांधी के व्यक्तित्व को मिटाने की एक सुनियोजित विकृत मानसिकता एवं साजिश है। गांधी की प्रतिमा महज धातु का ढांचा नहीं, बल्कि उन मूल्यों का जीवंत प्रतीक है जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को नई दृष्टि दी, नई दिशा दी एवं शांतिपूर्ण अहिंसक जीवनशैली दी है। इस पर आघात करना इस बात का प्रमाण है कि हिंसा की प्रवृत्तियां, आतंक की मानसिकता एवं नफरत-द्वेष की विध्वंक शक्तियां अब भी गांधी के विचारों से डरती हैं और उसे क्षत-विक्षत एवं ध्वस्त करने के षडयंत्र रचती रहती है, पर महात्मा गांधी भारत के अकेले ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें कोई गोली या गाली नहीं मार सकती। गांधी की राजनीति व धर्म का आधार सत्ता नहीं, सेवा था, वसुधैव कुटुम्बकम् था। जनता को भयमुक्त व वास्तविक आजादी दिलाना उनका लक्ष्य था। वे सम्पूर्ण मानवता की अमर धरोहर हैं। उन्होंने दुनिया को अहिंसा का सूत्र देकर शांतिपूर्ण विश्व-संरचना की। दलितों के उद्धार और उनकी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उनके जीवन की विशेषता कथनी और करनी में अंतर नहीं होना था। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अज्ञात लोगों ने जो हमला किया और आपत्तिजनक नारे लिखे। भारतीय उच्चायोग ने इसे अहिंसा की विरासत पर हमला बताया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस जांच में जुटी है। ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि गांधी की शिक्षाएं हमें सदा एकजुट करती रहेंगी। गांधी के व्यक्तित्व एवं विचारों को आहत करने की यह घटना केवल ब्रिटेन के अस्तित्व एवं अस्मिता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भारत की गरिमा और उसकी सांस्कृतिक उपस्थिति को भी चुनौती देती है। जब किसी राष्ट्र के सार्वभौमिक प्रतीक पर हमला होता है, तो वह उस राष्ट्र के स्वाभिमान और उसके विचारों पर हमला माना जाता है। गांधी केवल भारत के नायक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के नैतिक मार्गदर्शक हैं। उनका स्मारक क्षतिग्रस्त करना मानवता की उस चेतना को धूमिल करने का प्रयास है जो संवाद, सहिष्णुता, अहिंसा और शांति पर आधारित है। ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध, आतंक और कट्टरता से त्रस्त है, गांधी का विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। ऐसे विचार को कुचलने की चेष्टा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों अहिंसा जैसे सार्वभौमिक मूल्य आज के दौर में असहनीय प्रतीत होते हैं? क्यों कुछ समूह इतिहास को मिटाने और संवाद की जगह हिंसा को स्थापित करने पर आमादा हैं? यह केवल अतीत की स्मृति पर हमला नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा पर भी सवाल खड़ा करता है। मूर्तियां टूटीं तो उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन यदि विचारों को खंडित करने का यह सिलसिला जारी रहा तो यह मानवता की आत्मा के लिए घातक सिद्ध होगा। समय-समय पर शरारती एवं असामाजिक तत्व देश एवं दुनिया में भारत की महान् विभूतियों- गांधी-मोदी के दर्शन व उनकी कार्य-पद्धतियों पर कीचड़ उछालते रहे हैं और उन्हें गालियां देकर गौरवान्वित होते रहे हैं। ताजा गांधी प्रतिमा को तोड़ने की घटना किसी साधारण शरारत या स्थानीय असंतोष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस गहरी हिंसक, आतंकी और विकृत मानसिकता का प्रतीक है, जो दुनिया में अहिंसा की आवाज़ को दबाना चाहती है। यह घटना केवल एक प्रतिमा को खंडित करने की नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के विचारों पर आहत करने की साजिश है। गांधी महज एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दर्शन हैं। उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत विश्व राजनीति, समाज और मानवता के लिए अब भी सबसे बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। इसीलिए हिंसक मानसिकताएं बार-बार इन मूल्यों को मूक बनाने या कुचलने का प्रयास करती हैं। गांधी प्रतिमा पर हमला वस्तुतः उसी मानसिकता की पुनरावृत्ति है, जिसने उनकी हत्या की थी। आज यह मानसिकता कभी धार्मिक उग्रवाद, कभी नस्लीय भेदभाव, कभी आतंकवाद और कभी आर्थिक साम्राज्यवाद का रूप धारण करके सामने आती है। यह घटना भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए गंभीर चेतावनी है कि यदि अहिंसा और सहअस्तित्व की आवाज़ को चुप करा दिया गया, तो मानव सभ्यता हिंसा, आतंक और विनाश के अंधकार में जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में जिस तरह शांति, वैश्विक सहयोग और अहिंसक संवाद की परंपरा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है, वह गांधी दर्शन की ही आधुनिक अभिव्यक्ति है। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों, जलवायु संकटों, आतंकवादी क्रूरताओं और युद्ध की विभीषिकाओं से जूझती दुनिया में भारत की यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में गांधी प्रतिमा पर हमला, दरअसल इस शांति अभियान को ठेस पहुँचाने का संगठित प्रयास है। यह केवल भारत को नहीं, बल्कि उन सभी देशों और समुदायों को चुनौती है, जो अहिंसा को सभ्यता का मूल मंत्र मानते हैं। आज यह जरूरी है कि हम इस हिंसक और आतंकवादी मानसिकता को करारा जवाब दें। यह जवाब केवल प्रतिवाद या आक्रोश से नहीं, बल्कि गांधी के विचारों को और अधिक दृढ़ता से जीकर और फैलाकर देना होगा। जब-जब गांधी प्रतिमा पर चोट की गई है, तब-तब गांधी और बड़े होकर खड़े हुए हैं। कभी-कभी प्रशंसा नहीं ऐसी गालियां गांधी को ज्यादा पूजनीय बनाती रही हैं। जिस प्रकार गांधी ने कहा था-"आप मुझे मार सकते हैं, मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, पर मेरे विचारों को समाप्त नहीं कर सकते"-यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दरअसल, अहिंसा को कुचलने की हर कोशिश अहिंसा को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। यह हमला गांधी की अमरता का प्रमाण है। हमें इस अवसर को केवल निंदा तक सीमित न रखकर, गांधी के सत्य, प्रेम और सहिष्णुता के संदेश को और व्यापक स्तर पर प्रसारित करना चाहिए। तभी आतंकवादी मानसिकता को वास्तविक और स्थायी जवाब मिलेगा। गांधी को कितने सालों से कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। जीते जी और मरने के बाद गांधी ने कम गालियां नहीं खाईं। गोडसे ने गोली से उनके शरीर को मारा पर आज तो उनके विचारों को बार-बार मारा जा रहा है। महात्मा के शिष्यों ने, बापू के बेटों ने, संत के अनुयायियों ने और गांधी की पार्टी वालों ने उनको बार-बार बेचा है, उनसे कमाया है, उनके नाम से वोट मांगे हैं, सत्ता प्राप्त की है, सुबह-शाम धोखा दिया है और उनकी चादर से अपने दाग छिपाये हैं। लेकिन बहुत हो गया, अब यह आवश्यक है कि इस घटना का विरोध केवल भावनात्मक या औपचारिक स्तर पर न होकर ठोस, नैतिक और प्रभावी स्वरूप में हो। आज गांधी को खोजने की जरूरत मूर्तियों में नहीं, बल्कि अपने जीवन और आचरण में है। यही इस घटना से निकला सबसे बड़ा संदेश है कि अहिंसा की रक्षा केवल स्मारकों से नहीं बल्कि व्यवहार से होगी। गांधी की प्रतिमा का क्षरण क्षणिक है, किंतु उनके विचारों की हत्या यदि हम होने देंगे तो यह सम्पूर्ण मानवता की हार होगी। लंदन में गांधीजी की इस प्रतिमा का अनावरण 1968 में इंडिया लीग के सहयोग से हुआ था। यूके में गांधी जयंती के मौके पर यह जगह लंबे समय से मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। हर साल 2 अक्टूबर को यहां फूलों से श्रद्धांजलि दी जाती है और गांधीजी के प्रिय भजन बजते हैं। इस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दे रखी है। इसके चबूतरे पर लिखा है-'महात्मा गांधी, 1869-1948'। उनका लंदन से ऐतिहासिक संबंध रहा है,जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की थी।

प्रेरणा

"लाल बहादुर शास्त्री : ईमानदारी और सादगी का अद्वितीय प्रतीक"

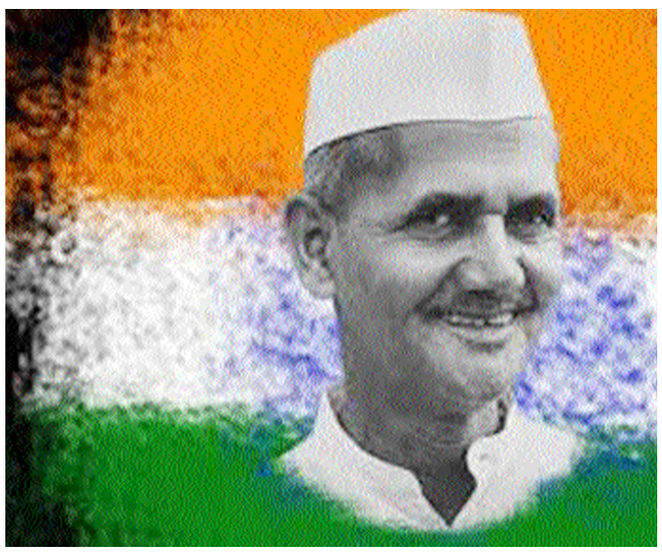

लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन सादगी, ईमानदारी और नैतिकता का ऐसा आदर्श था जिसकी मिसाल आज भी दुर्लभ है। उनका पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा नेतृत्व केवल पद और शक्ति से नहीं बल्कि सत्यनिष्ठा और त्याग से पहचाना जाता है। उनके जीवन की अनेक घटनाएँ इस बात को उजागर करती हैं कि उन्होंने कभी भी पद, प्रतिष्ठा या अधिकार का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया।

एक बार की घटना है जब शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के रेलवे मंत्री बने। उनके कार्यकाल में एक गंभीर रेल दुर्घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान चली गई। जैसे ही यह समाचार उन्हें मिला, उन्होंने तुरंत ही अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। नेहरू जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि दुर्घटनाएँ अचानक हो जाती हैं और मंत्री सीधे तौर पर उसके दोषी नहीं होते। लेकिन शास्त्री जी का मानना था कि मंत्री अपने विभाग के प्रत्येक कार्य और उसकी कमियों के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए उन्होंने अपने पद से हट जाना ही उचित समझा। यह घटना आज भी नेताओं की नैतिक ईमानदारी का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।

प्रधानमंत्री बनने के बाद भी शास्त्री जी का जीवन बिल्कुल आम आदमी की तरह ही रहा। 1965 में भारत-पाक युद्ध के दौरान देश में खाद्यान्न की भारी कमी हो गई थी। विदेश से आयात पर निर्भरता बढ़ रही थी। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने जनता से अपील की कि सप्ताह में एक दिन घर पर अनाज का उपयोग न करें, ताकि देश की बचत हो सके। लेकिन उन्होंने यह अपील केवल कहकर ही नहीं छोड़ी, बल्कि स्वयं और उनका परिवार भी हर सोमवार को बिना अनाज खाए उपवास रखने लगा। यह देखकर लोगों के मन में विश्वास जागा और उन्होंने पूरे उत्साह से इस अभियान में भाग लिया। शास्त्री जी का यह त्याग इस बात का प्रमाण था कि वे जनता से वही अपेक्षा रखते थे, जिसका पालन वे स्वयं पहले करते थे।

एक और प्रेरणादायक प्रसंग उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा है। जब वे प्रधानमंत्री थे, तब उनके घर पर एक कार की आवश्यकता पड़ी। प्रधानमंत्री होने के नाते वे चाहते तो सरकारी कोष से कार ले सकते थे या किसी कंपनी से उपहार स्वरूप पा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर कार खरीदी। इतना ही नहीं, उनके निधन के बाद भी वह कर्ज बाकी था जिसे उनकी पत्नी ने नियमित रूप से चुकाया। यह घटना बताती है कि शास्त्री जी पद पर रहते हुए भी अपने निजी जीवन को सरकारी सुविधाओं से अलग रखते थे और कभी भी जनता के धन को व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे।

उनकी सादगी का एक और जीवंत दृश्य तब देखने को मिला जब वे प्रधानमंत्री आवास में रहने लगे। उनका परिवार पहले की तरह ही सामान्य जीवन जीता। उनके बच्चे स्कूल रिक्शे से जाते थे और परिवार का खर्च भी सादगीपूर्ण ढंग से चलता था। उन्होंने कभी भी सुरक्षा या पद का दिखावा नहीं किया।

लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन वास्तव में ईसादा जीवन, उच्च विचारर का जीवंत उदाहरण है। उनकी ईमानदारी केवल राजनीतिक आचरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उतनी ही गहरी थी। उनके शब्दों और कर्मों में कोई अंतर नहीं था। इसीलिए वे आज भी भारतीय राजनीति में सबसे ईमानदार और प्रेरक नेताओं में गिने जाते हैं।

वृद्ध बोझ नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के संरक्षक हैं

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिवस का उद्देश्य वृद्धों के अधिकारों, उनकी गरिमा और उनके योगदान को रेखांकित करना है। यह दिन हमें यह सोचने को विवश करता है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव में, जिसे कभी सम्मान और अनुभव का प्रतीक माना जाता था, आज वह उपेक्षा, अकेलेपन और असुरक्षा का पर्याय क्यों बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2030 तक 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग पूरी दुनिया में 1.4 अरब से अधिक हो जाएंगे और 2050 तक यह संख्या दोगुनी होकर लगभग 2.1 अरब तक पहुँच जाएगी। विकसित देशों में वृद्धजन आबादी का चौथाई हिस्सा बन चुके हैं, वहीं विकासशील देशों में भी उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन विडंबना यह है कि इस बढ़ती जनसंख्या के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक भागीदारी की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में वृद्धजन पेंशन और हेल्थकेयर से तो सुरक्षित हैं, परंतु वहाँ अकेलेपन और मानसिक अवसाद की समस्या विकराल है। एशिया और अफ्रीका में, जहां परिवार व्यवस्था मजबूत मानी जाती थी, अब संयुक्त परिवार टूटने से वृद्धजन आर्थिक व सामाजिक असुरक्षा से जूझ रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरुआत 1991 में हुई थी और इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र की आबादी के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा वृद्धजनों के अधिकारों और योगदान को पहचानना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस पर वृद्धजनों को समर्थन देने वाली प्रणालियों को मज़बूत करने का आह्वान किया जाता है और उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाता है। समाज में उनके बहुमूल्य योगदान को मान्यता देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, वृद्धजनों को स्वास्थ्य सेवाएं, देखभाल, सामाजिक सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मज़बूत करना, वृद्धजनों को वैश्विक विकास प्रयासों में शामिल करना और शहरी वातावरण को उनके लिए अधिक समावेशी बनाना आदि इस दिवस को मनाने के उद्देश्य हैं। इस दिवस को मनाते हुए वृद्ध व्यक्तियों की डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच प्रदान करने के महत्व पर जोर देना और यह सुनिश्चित करना कि सभी आयु वर्गों के लिए समानता को बढ़ावा दिया जाए और वृद्ध व्यक्तियों के मानवाधिकारों का पालन हो आदि बातों पर विशेष बल दिया जाता है।

इस दिवस की 2025 की थीम 'समावेशी भविष्य के लिए वृद्धजनों की आवाज़ को सशक्त बनाना' है, जो वृद्धजनों की आवाज़, अनुभव और ज्ञान को पहचानने तथा उनके अनुभवों के आधार पर समावेशी समाजों के निर्माण पर जोर देती है। यह थीम इस बात पर प्रकाश डालती है कि वृद्धजन लचीले और समतामूलक समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्नत एवं आदर्श समाज के निर्माण में वृद्धजनों की आवाज़, उनके दृष्टिकोण और अनुभव को विशेष महत्व है। वृद्धावस्था में कठिनाइयां अनेक रूपों में सामने आती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय रोग, मधुमेह, जोड़ों के दर्द और डिमेंशिया जैसी बीमारियाँ उन्हें घेरे रहती हैं, परंतु चिकित्सा सुविधाओं तक उनकी पहुंच सीमित है। आर्थिक दृष्टि से पेंशन व सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हर वृद्धजन तक नहीं पहुँचतीं और ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी दयनीय है। सामाजिक स्तर पर आधुनिक जीवन की दौड़ में वृद्धजन अकेलेपन, उदासी और उपेक्षा से पीड़ित हैं। मानसिक दृष्टि से आत्मसम्मान को ठेस, भूमिका से वंचित होना और बेकारपन का एहसास उन्हें भीतर तक तोड़ देता है।

भारत में वृद्धों की स्थिति अधिक चिन्ताजनक है। जबकि वृद्धजन भारतीय समाज की धरोहर मानी जाती रही हैं, उन्हें अनुभव और ज्ञान का भंडार मानते हैं। इसके बावजूद यदि हम उन्हें उपेक्षित करेंगे तो यह केवल अन्याय ही नहीं, बल्कि सभ्यता एवं संस्कृति की पराजय होगी। वृद्धजन केवल जीवित बोझ नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के संरक्षक हैं। उनका सम्मान करना न केवल हमारा नैतिक कर्तव्य है बल्कि एक बेहतर, संवेदनशील और संतुलित समाज के निर्माण की अनिवार्यता है। भारत जैसे विकसित देश के नागरिकों की औसत आयु 60 वर्ष से अधिक 65 हो रही है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण देश में वृद्धजन की संख्या बढ़ रही है, देश में 2011 में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक थे, जिनके 2050 तक बढ़कर 30 करोड़ होने का अनुमान है। अनुमान है, कि 2050 तक हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। यह बात भारत के नीति आयोग ने कही है, इसी के कारण बुजुर्गों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

भारत में परंपरागत भारतीय परिवार व्यवस्था में वृद्धजनों को सम्मान, सुरक्षा और निर्णय लेने की अहम भूमिका प्राप्त थी। लेकिन आज शहरीकरण, परमाणु परिवार, प्रवास और उपभोक्तावादी सोच ने उनकी भूमिका को हाशिए पर पहुँचा दिया है। परिवार के भीतर उन्हें आर्थिक बोझ समझा जाने लगा है, पीढ़ीगत टकराव और मूल्यों में बदलाव ने दूरी बढ़ा दी है, नौकरी-पेशा बच्चों के व्यस्त जीवन में धैर्य और देखभाल की कमी स्पष्ट हो रही है और संपत्ति तथा अधिकारों को लेकर तनाव आम हो गया है।

अभियान

दशहरा: अधर्म पर धर्म की विजय और आत्मशुद्धि का संकल्प

विजयादशमी अर्थात् दशहरा भारतीय संस्कृति का वह पावन पर्व है जो हर वर्ष हमें यह स्मरण कराता है कि असत्य और अधर्म चाहे कितने ही बलशाली क्यों न प्रतीत हों, उनकी विजय कभी स्थायी नहीं हो सकती। सत्य, धर्म और न्याय की ही अंततः विजय होती है। यह पर्व केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का दर्पण और भविष्य का मार्गदर्शन भी है।

दशहरे से जुड़े दो महान प्रसंग हमें धर्म की महत्ता और शक्ति का बोध कराते हैं। पहला प्रसंग है भगवान श्रीराम का लंका विजय और रावण वध। रावण अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और शक्तिशाली था, किंतु उसका अहंकार और अन्याय उसे विनाश की ओर ले गया। जब उसने माता सीता का हरण किया और धर्म के मार्ग से भटका, तब श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए उसका संहार किया। दूसरा प्रसंग है मां दुर्गा का महिषासुर पर विजय पाना। महिषासुर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर संसार में आतंक फैला रहा था, किंतु अंततः वह भी देवी दुर्गा की दिव्य शक्ति के आगे पराजित हुआ। इन दोनों घटनाओं का संदेश यही है कि अधर्म और अन्याय कितने भी प्रबल क्यों न हों, धर्म और सत्य के सामने उनका अंत निश्चित है।

दशहरा केवल पुरानी घटनाओं का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। रावण के दस सिर हमारे दस दोषों का प्रतीक हैं, जिन्हें हमें हर दशहरे पर जलाना चाहिए। यही आत्मशुद्धि का संकल्प है। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महान है। उत्तर भारत में रावण दहन की परंपरा हमें यह स्मरण कराती है कि अधर्म अंततः नष्ट होता है। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शक्ति के सम्मान और जीवन में पवित्रता का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इस दिन विद्या और कला की पूजा होती है, जो यह सिखाती है कि ज्ञान और संस्कृति ही जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार दशहरा सम्पूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधता है और धर्म, सत्य तथा शक्ति का अद्वितीय संदेश देता है। आज जब समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, अन्याय और असत्य की शक्तियाँ सक्रिय हैं, तब दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हम न केवल हमारे भीतर भी एक रावण छिपा हुआ है—अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह और अनैतिक इच्छाओं के रूप में। जब तक हम अपने अंदर छिपे इन दोषों का दहन नहीं करेंगे, तब तक सच्ची विजय संभव नहीं है। बाहरी बुराई का विरोध करें, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को भी परास्त करें। श्रीराम की तरह मर्यादा और धर्म का पालन करें, और मां दुर्गा की तरह साहस और शक्ति के साथ अन्याय का नाश करें। दशहरे का वास्तविक संदेश यही है कि हम जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग लोककल्याण में करें, न कि स्वार्थ और अहंकार में। जब हम अपने भीतर के दोषों का दहन करेंगे और प्रेम, करुणा व सद्भावना का संचार करेंगे, तभी यह पर्व हमारे जीवन में सार्थक होगा।

आज जब हम रावण के पुतले जलाएँगे, तो यह केवल परंपरा न रह जाए, बल्कि आत्मशुद्धि का एक संकल्प बने। हम प्रण लें कि हम सत्य का साथ देंगे, धर्म का पालन करेंगे और अन्याय का विरोध करेंगे। यही दशहरे की आत्मा है और यही इस महापर्व का वास्तविक उद्देश्य है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद को हाई सिक्योरिटी में झांसी जेल में किया गया स्थानांतरित

(जीएनएस)। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे अली अहमद को नैनी जेल से झांसी जिला जेल में हाई सिक्योरिटी के बीच बुधवार को स्थानांतरित किया गया। अली लगभग 38 महीने से नैनी जेल में बंद थे और अब प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के बीच उन्हें झांसी जेल में लाया। प्रयागराज से झांसी तक 420 किलोमीटर की इस यात्रा में पुलिस ने हर कदम पर कड़ा पहरा रखा। दोपहर 3.10 बजे जब प्रिजन वैन झांसी जेल पहुंची, अली को तुरंत तन्हा बैरक में रखा गया, जबकि उसकी पूरी तलाशी और सुरक्षा चेकिंग पहले ही की जा चुकी थी।

झांसी पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में अली अहमद ने बताया कि वे यात्रा के दौरान गाड़ी में केवल पांच-छह लोगों के साथ थे और पूरे समय पानी तक नहीं पी पाए। उन्होंने प्रशासन और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि उन्हें परेशान करने वाले लोगों से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अली ने यह भी कहा कि वह लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया।

सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा की प्रक्रिया

अली को मंगलवार रात शासन के आदेश के बाद बुधवार सुबह 6.10 बजे नैनी जेल से झांसी के लिए रवाना किया गया। यात्रा मार्ग पर हाई सिक्योरिटी और पुलिस अलर्ट व्यवस्था सुनिश्चित की गई। झांसी सीमा में बस स्टैंड से कचहरी चौराहा तक मार्ग की रफ्तार घटाकर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई। पुलिस और जेल प्रशासन ने इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया।

अली अहमद को प्रॉपर्टी डीलर जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी व यूपी के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था। अली ने 30 जुलाई 2022 को कोर्ट में सरेंडर किया था। उनकी गिरफ्तारी और जेल में बंदी की अवधि के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

झांसी जेल में तन्हा बैरक में रखा गया

झांसी के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि जेल नियमों के अनुसार अली को सेल में रखा गया है। उन्हें जेल गेट से भीतर प्रवेश कराने के बाद पूरी तलाशी के बाद तन्हा बैरक में रखा गया। फिलहाल उनकी सुरक्षा और निगरानी का विशेष इंतजाम किया गया है। जेल प्रशासन ने कहा कि अली अहमद की सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके संपर्क में नहीं आएगा। यह स्थानांतरण राज्य में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की गंभीर रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उच्च सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन के कड़े कदमों से यह सुनिश्चित किया गया है कि अली अहमद के साथ कोई अप्रिय घटना न हो और उनके जेल जीवन की निगरानी प्रभावी रूप से हो।

तमिलनाडु में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप, दो गिरफ्तार

(जीएनएस)। तिरुवन्नामलाई। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में एक चौकस और गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें तिरुवन्नामलाई ईस्ट पुलिस स्टेशन के दो पुलिसकर्मी पर आंध्र प्रदेश की एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। यह जानकारी तिरुवन्नामलाई ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन की एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

घटना की पूरी कहानी

शिकायत के अनुसार, सोमवार शाम पीड़िता अपनी मां के साथ अरुलमिगु अरुणाचलेश्वरर मंदिर में पूजा करने के लिए एक वाहन से जा रही थीं। जैसे ही वे तिरुवन्नामलाई बाईपास रोड पर पहुँचीं, वाहन चेकिंग के नाम पर ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों ने उन्हें वाहन से उतरने को कहा। इसके बाद आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को एक सुनसान जगह ले जाकर कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

तुरंत कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। पीड़िता की शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मामले की पूरी तरह जांच की जाएगी और दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और सुरक्षा

तिरुवन्नामलाई पुलिस प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा और सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, पुलिसकर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था की जाएगी।

मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया है और नागरिक समाज द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि इस घटना की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी होगी और दोषियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

बरेली बवाल: डॉ. नफीस और उसके बेटे सहित आठ आरोपियों को जेल भेजा गया, अब तक 81 गिरफ्तार

(जीएनएस)। बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में 26 सितंबर को हुई हिंसक घटना के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई जारी रखी है। बुधवार को डॉ. नफीस खां और उनके बेटे फरमान सहित आठ और आरोपियों को जेल भेजा गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आठों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दो आरोपी मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए। ये दोनों शाहजहांपुर जनपद के रहने वाले हैं। इस हिंसक घटना के बाद अब तक कुल 81 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

पुलिस ने बताया कि फुटेज और वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। जांच का मुख्य फोकस उन लोगों पर है, जिन्होंने भीड़ को जुटाने और उकसाने की कोशिश की। एसएसपी अनुराग आर्य के अनुसार, 26 सितंबर को नमाज का समय बदला गया था। आमतौर पर यहां जुमे की नमाज साढ़े 12 बजे से पौने चार बजे तक होती है, लेकिन मौलाना तौकीर का वीडियो वायरल होने के बाद संदेश फैलाया गया कि नमाज एक बजे होगी। इससे अधिक से अधिक भीड़ इस्लामिया मैदान की तरफ पहुंच गई। इस घटना में शामिल तीन आरोपी दूसरे राज्यों के हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है।

हिंसा और तोड़फोड़ की पूरी कहानी

बवाल उस समय शुरू हुआ जब "आई लव मोहम्मद" के समर्थन में इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने लोगों को बुलाया। मौलाना की गैरमौजूदगी में भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई। पुलिस ने बताया कि लोगों ने दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान 22 पुलिसकर्मी घायल हुए।

बवाल के बाद शहर के विभिन्न थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें कुल 125 नामजद और करीब तीन हजार अज्ञात आरोपी शामिल हैं। सात मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम भी दर्ज है। इस घटना की जांच के लिए डीआईजी रेंज अजय कुमार साहनी के निर्देश पर एसएसपी अनुराग आर्य ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी में एसपी सिटी मानुष पारीक के नेतृत्व में तीन सीओ और 14 इंस्पेक्टर शामिल हैं।

एसएसपी ने बताया कि जिले में धारा 163 लागू है, जिसका पूरी तरह पालन कराया जाएगा। पुलिस का दावा है कि बवाल के पीछे साजिश के तत्व थे और प्रशासन इस मामले में किसी को भी कानून के दायरे से बाहर नहीं रहने देगा। इस कार्रवाई के साथ ही बरेली प्रशासन ने संदेश दिया है कि हिंसा और उकसाने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

वडोदरा रेल मंडल में "स्वच्छता पखवाड़ा – 2025" का शुभारंभ

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में 01 से 15 अक्टूबर 2025 तक "स्वच्छता पखवाड़ा – 2025" का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य स्वच्छता को जन-आंदोलन के रूप देना तथा रेलवे परिसरों एवं यात्री सुविधाओं में स्वच्छता को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाना है।

आज दिनांक 01 अक्टूबर 2025 को "स्वच्छता पखवाड़ा" का शुभारंभ शपथग्रहण समारोह एवं प्रभात फेरी के साथ किया गया। अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज धमीजा के नेतृत्व में वडोदरा यार्ड स्थित बच्चों के पार्क में शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ.दीपाली तिवारी तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजिनियर श्री अनिल कुमार सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और अभियान को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के तहत स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने हेतु प्रभात फेरी का आयोजन भी किया गया। यह फेरी मैकेनिकल ट्रेनिंग स्कूल से प्रारंभ होकर बच्चों के पार्क तक संपन्न हुई, जिसमें रेलकर्मी एवं स्काउट-गाइड्स के सदस्य उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

इस अवसर पर बच्चों के पार्क में फिक्की वडोदरा के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। डॉ.दीपाली तिवारी ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए वृक्षारोपण को वायु गुणवत्ता सुधार का प्रभावी साधन बताया। श्री नीरज धमीजा ने जानकारी दी कि फिक्की एवं पश्चिम रेलवे के बीच हुए समझौते (MoU) के अंतर्गत इस वर्ष मंडल के विभिन्न स्थलों पर 3000 से 6000 पौधे लगाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारियों एवं रेल आवासीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए एमटीयू परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया।

इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

करुर हादसे के बाद विजय रथ रुका, टीवीके ने रैलियों को दो हफ्तों के लिए स्थगित किया

(जीएनएस)।

करुर। तमिल अभिनेता और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) पार्टी प्रमुख विजय की करुर रैली में हुई भगदड़ की त्रासदी का असर अब उनकी सभी आगामी गतिविधियों पर दिखाई दे रहा है। 27 सितंबर को हुई इस जनसभा में 41 लोग मारे गए और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। भीड़ को नियंत्रित करने में बड़ी चूक सामने आई और बड़ी संख्या में लोग दबकर अपनी जान गंवा बैठे।

इस हादसे के बाद पार्टी ने अगले दो हफ्तों के लिए विजय की सभी रैलियों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। टीवीके के मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि करुर की यह त्रासदी सबको हिला देने वाली थी और ऐसे माहौल में कार्यक्रम जारी रखना उचित नहीं होगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि विजय की "जनता से मिलो" पहल के तहत हर शनिवार आयोजित होने वाली रैलियां आगामी दो हफ्तों तक नहीं होंगी। विजय अब तक तिरुचिरापल्ली, नमक्कल और करुर का दौरा कर चुके हैं। रैलियों की नई तारीखों की घोषणा केवल विजय की मंजूरी के बाद ही की जाएगी।

टीवीके की सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि पार्टी अपने 41 साथियों की मृत्यु पर गहरे दुख और व्यथित है। इस मुश्किल समय में पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। विजय ने भी घायलों के इलाज और पीड़ित परिवारों की मदद के लिए कदम उठाने की घोषणा की है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस निर्णय को "संवेदनशील और जिम्मेदार" कदम बताया है। करुर की त्रासदी न केवल टीवीके पार्टी पर बल्कि तमिलनाडु की राजनीति पर भी गहरा असर डाल चुकी है। अगली रैलियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किए जाने के बाद ही सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अहमदाबाद मंडल पर "स्वच्छता पखवाड़ा – 2025" का शुभारंभ

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक "स्वच्छता पखवाड़ा – 2025" का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े का उद्देश्य स्वच्छता को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन का रूप देना है, जिससे रेलवे परिसरों, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल और अन्य यात्री सुविधाओं में सफाई और अधिक प्रभावी और सतत बनी रहे।

दिनांक 01.10.2025 को "स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ मंडल कार्यालय में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम और प्रभात फेरियों के साथ किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वच्छता रखने की शपथ दिलाई और पखवाड़े के सफल आयोजन तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सभी कर्मचारियों को प्रेरित किया। मंडल के अहमदाबाद, साबरमती, पालनपुर, गांधीधाम, महेसाणा सहित विभिन्न स्टेशनों पर भी शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 2000 से अधिक रेल कर्मचारियों ने भाग लिया और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली।

इसके अतिरिक्त रेलवे परिसरों और प्लेटफॉर्म पर सफाई के महत्व के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान मण्डल के विभिन्न स्थानों पर 500 से अधिक कर्मचारियों ने श्रमदान कर रेल परिसरों को स्वच्छ किया और यात्रियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया।

"स्वच्छता पखवाड़ा–2025" के अंतर्गत अहमदाबाद मंडल आगामी दिनों में विशेष स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता कार्यक्रम, निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ, तथा यात्रियों को स्वच्छता का संदेश देने हेतु विविध प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ आयोजित करेगा।

अहमदाबाद मंडल का मानना है कि स्वच्छता केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। इस पखवाड़े के माध्यम से रेलवे न केवल अपने परिसरों को साफ-सुथरा बनाएगा बल्कि यात्रियों और आम जनता में स्वच्छता के महत्व को भी जागरूक करेगा।

पश्चिम रेलवे ने ईएमयू और ट्रैक्शन रखरखाव में महिला शक्ति को आगे बढ़ाया

(जीएनएस)। शहर की रफ़्तार के पीछे समर्पित महिलाएँ: पश्चिम रेलवे की महिला टीम कारशेड में ईएमयू रेक्स के महत्वपूर्ण रखरखाव कार्य सूक्ष्मता और समर्पण के साथ करती हैं, जिससे सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित होता है। पश्चिम रेलवे मुंबई के उपनगरीय रेल नेटवर्क को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाकर मानदंडों को पुनर्परिभाषित और समावेशिता को बढ़ावा दे रही है। अत्याधुनिक ईएमयू रेकों के रखरखाव से लेकर हाई-वोल्टेज ट्रैक्शन प्रणालियों के प्रबंधन तक, महिला तकनीशियन उन भूमिकाओं में कदम रख रही हैं, जिन्हें कभी पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था और यह साबित कर रही हैं कि विशेषज्ञता और समर्पण लिंग-भेद से परे हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल, कांदिवली और विरार में स्थित ईएमयू कारशेड मुंबई की जीवन रेखा के रखरखाव की रीढ़ हैं। ये कारशेड यातायात की माँग के अनुसार ईएमयू रेकों के सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे संचालित होते हैं, जहाँ 112 रेकों पर अनुसूचित और अनिर्धारित दोनों तरह के रखरखाव किए जाते हैं। अत्याधुनिक 3-फेज एसी (25 केवी अल्टरनेटिंग करंट) तकनीक वाले ये रेक क्रमशः 60 और 240 दिनों के अंतराल पर दो प्रमुख रखरखाव अनुसूचियों, आईए और आईसी, से गुजरते हैं। इन अनुसूचियों के दौरान कुल 45 गतिविधियाँ की जाती हैं, जिनमें से तीन प्रमुख कार्यों में सुरक्षा मंजूरी का मापन, तेल लगाना और बैटरी जाँच शामिल हैं। इन प्रमुख केंद्रों पर समर्पित महिला टीमों की तैनाती एक उल्लेखनीय विशेषता है। मुंबई सेंट्रल, कांदिवली और विरार स्थित ईएमयू कारशेड में तैनात लगभग 100 महिला तकनीशियनों और पर्यवेक्षकों को ये महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। ये टीमें सुनिश्चित करती हैं कि सभी सुरक्षा मानदंड आरडीएसओ द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमाओं के भीतर हों और ल्यूब्रिकेंट एवं बैटरी संबंधी सभी गतिविधियाँ सटीकता और दक्षता के साथ संपन्न हों। कुशल, सतर्क और शून्य विफलताओं को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध, ये महिलाएँ पश्चिम रेलवे की परिचालन उत्कृष्टता की खोज का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे के मुंबई उपनगरीय कर्षण (टीआरडी) विभाग ने महालक्ष्मी कर्षण सबस्टेशन पर शहर की पहली महिला-प्रधान रखरखाव टीम की स्थापना की है, जिसने लैंगिक समावेशन में एक नया मानक स्थापित किया है। रखरखाव टीमें विश्वसनीय उपनगरीय ट्रेन संचालन की रीढ़ होती हैं क्योंकि ये टीमें एसी कर्षण प्रणाली में बिजली आपूर्ति प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करती हैं। इस महिला-प्रधान इकाई ने सबस्टेशन पर 25 केवी और 110 केवी उपकरणों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है और अब इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए आधिकारिक तौर पर तैनात किया गया है। यह अभूतपूर्व पहल बदलती सामाजिक गतिशीलता को रेखांकित करती है। इस टीम का गठन न केवल पश्चिम रेलवे के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि तकनीकी और परिचालन क्षेत्रों में विविधता के प्रति इसकी प्रगतिशील दृष्टि और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की भूमिकाओं में महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाकर, पश्चिम रेलवे परिवर्तन को प्रेरित करता है और एक अधिक समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

रेलवे उपकरणों का बड़ा निर्यातक बन रहा है भारत

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत बोगियों, कोचों, लोकोमोटिव और प्रणोदन प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण रेलवे उपकरणों के वैश्विक निर्यातक के रूप में तेज़ी से उभर रहा है। यह बढ़ता निर्यात क्षेत्र भारत की डिज़ाइन, विकास और मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड को दर्शाता है। भारत के रेलवे उत्पाद तेजी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। मेट्रो कोच ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को निर्यात किए गए हैं, बोगियां ब्रिटेन, सऊदी अरब, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को, प्रणोदन प्रणालियां फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया, स्पेन, जर्मनी और इटली को, यात्री कोच मोजाम्बिक, बांग्लादेश और श्रीलंका को, तथा लोकोमोटिव मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और गिनी गणराज्य को निर्यात किए गए हैं।जून 2025 में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मढ़ौरा लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र से गिनी गणराज्य के लिए निर्यात हेतु पहले इंजनों को हरी झंडी दिखाई। अब तक, मढ़ौरा में निर्मित 6 इंजनों का सफलतापूर्वक निर्यात किया जा चुका है। हाल ही में, ये इंजन गिनी गणराज्य पहुंच गए हैं। मढ़ौरा प्लांट ने इवोल्यूशन सीरीज़ के इंजनों के निर्यात के लिए दूसरा रणनीतिक ऑर्डर हासिल कर लिया है, जिससे अफ्रीका के लिए कुल निर्यात लगभग 150 इकाइयों का हो गया है। 4,500 एचपी इवोल्यूशन सीरीज़ इंजन से युक्त ये लोकोमोटिव, अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ईंधन दक्षता और उच्च तापमान वाले वातावरण में भी सिद्ध प्रदर्शन प्रदान करते हैं। ये लोकोमोटिव भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की मांगों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाते हैं। बिहार में मढ़ौरा संयंत्र की सफलता रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी का प्रमाण है, जो नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक रेलवे आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावी योगदान देने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

अहमदाबाद मंडल में रेलवन ऐप का सफल संचालन – यात्रियों को मिल रही रेलवन ऐप से सुविधाजनक डिजिटल सेवाएँ

भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विकसित की गई आधुनिक तकनीक आधारित रेलवन ऐप (Railone App) अहमदाबाद मंडल में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। यह ऐप यात्रियों को पूरे वर्ष सुविधाजनक सेवाएँ प्रदान करता है और विशेष रूप से दुर्गापूजा, दशहरा, दीपावली, और छठपूजा जैसे त्योहारी मौसम में भारी भीड़ के बीच सुगम यात्रा सुनिश्चित कर रहा है।

रेलवन ऐप — एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रमुख सेवाएँ

भारतीय रेल का नवीनतम रेलवन ऐप पुराने रेलकनेक्ट एवं यूटीएस ऐप को एकीकृत करता है और एंड्रॉयड व आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। यह यात्रियों को एक ही मंच पर सभी प्रमुख डिजिटल सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे यात्रा का अनुभव और भी सहज बनता है।

रेलवन ऐप की प्रमुख विशेषताएँ :

- आरक्षित, अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग एक ही ऐप में।
- ट्रेन के वास्तविक समय, लाइव लोकेशन एवं आगमन-प्रस्थान की जानकारी।
- पीएनआर स्टेटस एवं कोच पोजिशन की सुविधा।
- 'माई बुकिंग्स' में सभी टिकटों का रिकॉर्ड एक जगह।
- यात्रा के दौरान भोजन बुकिंग की सुविधा।
- पार्सल एवं फ्रेट ट्रैकिंग की आधुनिक प्रणाली।
- 'रेल मदद' से शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने की सुविधा।
- एम-पिन एवं बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/फेस आईडी) लॉगिन विकल्प।
- सभी आयु वर्ग के लिए सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफ़ेस।

रेलवन ऐप के प्रमुख लाभ :

- सभी सेवाएँ एक मंच पर उपलब्ध।
- मोबाइल स्टोरेज की बचत।
- तेज़, सहज एवं पर्यावरण अनुकूल डिजिटल सेवा।
- पुराने अकाउंट से लॉगिन पर पुरानी बुकिंग एवं डेटा का स्वतः समावेश।
- बेहतर यात्री अनुभव एवं परेशानी मुक्त यात्रा।

अहमदाबाद मंडल यात्रियों से अपील करता है कि वे अपनी यात्रा को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित एवं आधुनिक बनाने के लिए रेलवन ऐप का अधिकाधिक उपयोग करें। यात्री रेलवन ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और डिजिटल यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।

राजनाथ सिंह भुज में जवानों संग दशहरा मनाएंगे, करेंगे शस्त्र पूजा, बढ़ेगा सैनिकों का मनोबल

(जीएनएस)। गुजरात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 अक्टूबर को भुज सैन्य अड्डे पर भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरा उत्सव मनाने के लिए बुधवार को गुजरात के भुज पहुंचे। इस अवसर पर वे न केवल दशहरा मनाएंगे, बल्कि शस्त्र पूजा भी करेंगे, जिससे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता की भावना से भी प्रेरित किया जाएगा। रक्षा मंत्री का भुज वायु सेना स्टेशन पर थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने स्वागत किया।दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में शामिल है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम द्वारा राक्षस राजा रावण पर विजय को याद

किया जाता है। यह त्योहार न केवल अहंकार, लोभ, अभिमान और ईर्ष्या जैसी आंतरिक बुराइयों पर विजय की प्रेरणा देता है, बल्कि सत्य, सदाचार और धर्म के मूल्यों को बनाए रखने का संदेश भी देता है। भुज में दशहरा मनाने से सैनिकों में राष्ट्रीय गर्व और सामूहिक अनुशासन की भावना को और मजबूती मिलेगी।

दोपहर में राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) की भूमिका की सराहना की। उन्होंने बताया कि डीएडी ने वित्तीय लचीलापन बनाए रखने, संसाधनों का अनुकूलन करने और परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने डीएडी को भारतीय सशस्त्र बलों की "मौन लेकिन महत्वपूर्ण रीढ़" बताया और कहा कि विभाग न केवल वित्तीय विवेक और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बल्कि समय पर संसाधनों की उपलब्धता से युद्ध और परिचालन तैयारियों को मजबूत बनाता है।

राजनाथ सिंह ने डीएडी की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और साहस देखा, लेकिन इसके साथ ही डीएडी की भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि सभी संसाधन कुशलता से और समय पर उपलब्ध हों। उनका मानना है कि इस तरह के उत्सव और शस्त्र पूजा समारोह सैनिकों के मनोबल और देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करेंगे।

भुज में दशहरा मनाने का यह कार्यक्रम न केवल हिंदू त्योहार की महत्ता को दर्शाता है, बल्कि भारतीय सेना के जवानों के लिए भी एक प्रेरक और उत्साहवर्धक आयोजन साबित होगा, जिससे उनकी वीरता, अनुशासन और कर्तव्यबोध की भावना को और मजबूती मिलेगी।

परफेक्ट टेन की तलाश: भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में पहले टेस्ट में

(जीएनएस)। अहमदाबाद। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम अब लाल गेंद के क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए तैयार है। गुरुवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मुकाबले में टीम की निगाह वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दसवीं सीरीज जीत पर है। पिछले 23 सालों में यह टीम अपने घरेलू मैदान पर इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अजेय रही है और पिछली नौ लगातार सीरीज में जीत हासिल की है। इस बार कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में भारतीय टीम हर संभव प्रयास करेगी कि इस क्रम को जारी रखा जा सके।

इस सीरीज में भारत का तीसरे स्थान पर होना इसे और महत्वपूर्ण बना देता है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ होने के बाद भारत ने तीसरे स्थान को बरकरार रखा है। वेस्टइंडीज इस डब्ल्यूटीसी चक्र में तीन टेस्ट हार चुकी है, जिससे भारतीय टीम के लिए सीरीज जीतना अपेक्षाकृत आसान नजर आता है। लेकिन भारतीय टीम संयम और रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी। अहमदाबाद की हरी-भरी पिचें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद करने वाली हैं, जिससे टीम को संयोजन में बदलाव पर विचार करना पड़ सकता है। भारतीय टीम का शीर्ष क्रम वही रहेगा, जिसमें केएल राहुल और यशस्वी जाधव ओपनिंग करेंगे, जबकि सुदर्शन तीसरे नंबर और कप्तान गिल चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल करने पर निर्णय हालात और विरोधी टीम की रणनीति के अनुसार होगा। विकेटकीपर की जिम्मेदारी ध्रुव जुरेल संभालेंगे। टीम में चार ऑलराउंडर हैं, जिनमें जडेजा, अक्षर पटेल, सुंदर और नितीश रेड्डी शामिल हैं। कलाई के जादूगर कुलदीप यादव तीसरे स्पिनर के रूप में खेल सकते हैं, जबकि तेज गेंदबाजी का मुख्य जिम्मा बुमराह और सिराज संभालेंगे। तीसरे पेसर के चयन में टीम प्रबंधन कृष्णा या नितीश रेड्डी पर विचार कर सकता है। वेस्टइंडीज के लिए राह आसान नहीं है। चोट के कारण उनके मुख्य पेसर शामार जोसेफ और अलजारी जोसेफ बाहर हैं।

'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष : देशभर में जश्न और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की मंजूरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी समारोह आयोजित करने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में 'वंदे मातरम्' ने लोगों को प्रेरित किया और यह गीत आज भी युवाओं और छात्रों के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों और युवा वर्ग को ऐतिहासिक घटनाओं और स्वतंत्रता संग्राम में गीत की भूमिका से परिचित कराया जाएगा। 'वंदे मातरम्' की रचना बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी और इसे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना गया। इसे राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के समकक्ष सम्मान प्राप्त है। यह गीत न केवल देशभक्ति का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता संघर्ष की पहचान भी बन गया है। कैबिनेट ने इसे 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में आयोजित होने वाले समारोहों के लिए मंजूरी दी, ताकि युवाओं में देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीय इतिहास के प्रति समझ विकसित हो।

साथ ही, कैबिनेट ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दी। यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों के आयात पर निर्भरता कम करना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है, लेकिन बढ़ती मांग के कारण आयात में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस मिशन के तहत बीज प्रणालियों, अनुसंधान, क्षेत्रीय विस्तार, खरीद और मूल्य स्थिरता को समग्र रणनीति के रूप में अपनाया जाएगा।

इस पहल के माध्यम से न केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। केंद्र सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और देश के किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके साथ ही, 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न से राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम न केवल ऐतिहासिक गीत की महत्ता को यादगार बनाने के लिए है, बल्कि आधुनिक भारत में आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने का भी प्रतीक है। देशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय कृषि प्रणाली की महत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है।

एशिया कप ट्रॉफी विवाद: एसीसी अध्यक्ष ने भारतीय टीम का स्वागत किया

दुबई। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बुधवार को कहा कि भारतीय टीम का एसीसी मुख्यालय में उनसे एशिया कप की ट्रॉफी लेने के लिए स्वागत है। यह बयान उस समय आया जब भारतीय टीम को एशिया कप जीतने के बावजूद पुरस्कार वितरण समारोह में ट्रॉफी न मिलने को लेकर विवाद बढ़ गया था।

मीडिया में आई खबरों का खंडन करते हुए नकवी ने कहा कि उन्होंने कभी बीसीसीआई से माफी नहीं मांगी और न ही कोई ऐसा व्यवहार किया जिससे विवाद उत्पन्न हो। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ₹एसीसी अध्यक्ष के तौर पर मैं उसी दिन ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर भारतीय टीम सच में ट्रॉफी चाहती है तो एसीसी कार्यालय आने के लिए उनका स्वागत है और वे इसे मुझसे ले सकते हैं।₹

यह विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रॉफी वितरण समारोह में भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था और

नकवी ने ट्रॉफी अपने पास रख ली थी। इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स आईं कि नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी थी, जिसे नकवी ने पूरी तरह खारिज किया।

बीसीसीआई ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के सामने उठाने का ऐलान किया है। आईसीसी की बैठक नवंबर में होगी, जिसमें इस विवाद का औपचारिक समाधान होने की उम्मीद है। इस बीच नकवी ने दोहराया कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और भारतीय टीम का एसीसी कार्यालय में स्वागत है, ताकि टीम ट्रॉफी प्राप्त कर सके। इस घटनाक्रम ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच भी उत्सुकता बढ़ा दी है कि ट्रॉफी आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों के हाथ कब पहुंचेगी और इस विवाद का समाधान किस रूप में होगा।

अभिषेक शर्मा ने टी-20 इतिहास की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की

दुबई। भारतीय क्रिकेट की नई युवा प्रतिभा अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर टी-20 क्रिकेट इतिहास में एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में अभिषेक के रेटिंग अंक अब 931 हो गए हैं, जो उन्हें टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाला बल्लेबाज बनाता है। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान का पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाज रहे। सात पारियों में उन्होंने 314 रन बनाए, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल थे और उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा। इस दौरान उनकी औसत 44.8 और स्ट्राइक रेट 200 रहा। इसके विपरीत, कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन के आंकड़े को पार नहीं कर सका। उनके बाद श्रीलंका के पथुम निसानका ने 261 रन बनाए। इस प्रदर्शन ने उन्हें न केवल टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनाया, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी टी-20 क्रिकेट में सर्वोच्च रेटिंग की उपलब्धि दिलाई।

टी-20 इतिहास में रेटिंग रिकॉर्ड की बात करें तो अभिषेक से पहले डेविड मलान ने 919 अंक हासिल किए थे, जो दिसंबर 2020 में उनका सर्वश्रेष्ठ था। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने जनवरी 2023 में 912 अंक हासिल किए। वहीं, विराट कोहली ने सितंबर 2014 में 909 रेटिंग अंक के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों के अलावा कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने भी अपनी स्थिति मजबूत की। पाकिस्तान के युवा ऑलराउंडर सैम अयूब ने 8 विकेट लेकर हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष रैंकिंग वाले ऑलराउंडर का खिताब अपने नाम किया। उनके 241 रेटिंग अंक हैं, जबकि हार्दिक पांड्या के 233 अंक हैं। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल इस समय 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने 803 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष स्थान बनाए रखा है। उन्होंने एशिया कप में 7 विकेट लिए थे। कलाई के जादूगर कुलदीप यादव ने भी अपनी रैंकिंग में 9 स्थान का सुधार किया और 12वें पायदान पर पहुँच गए। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और बांग्लादेश के रिशाद हुसैन भी क्रमशः 13वें और 20वें स्थान पर पहुँचकर अपने रैंकिंग अंक बढ़ाने में सफल रहे हैं।

अभिषेक शर्मा की यह उपलब्धि न सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय टी-20 टीम के युवा खिलाड़ियों की मजबूती और आगामी अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में उनकी उम्मीदों को भी नई ऊँचाई देगी।

मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, रबी फसलों के MSP में भारी वृद्धि

(जीएनएस)। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। यह कदम किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और कृषि को स्थिर तथा लाभकारी बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है।

सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए बताया कि कुसुम के लिए सबसे अधिक 600 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा, रेपसीड और सरसों के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 225 रुपये, जौ के लिए 170 रुपये

और गेहूं के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है।

एमएसपी में शामिल लागत का निर्धारण सभी किसानों द्वारा किए गए खर्चों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें मानव श्रम, बैल/मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि का किराया, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई शुल्क, उपकरण और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, पंप सेटों के संचालन के लिए डीजल/बिजली आदि सभी खर्च शामिल हैं। इसके साथ ही परिवार के श्रम का अनुमानित मूल्य भी इसमें शामिल किया गया है।

यह वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित नीति के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किया जाएगा। इस आधार पर गेहूं के लिए अपेक्षित मार्जिन 109 प्रतिशत, रेपसीड और सरसों के लिए 93 प्रतिशत, मसूर के लिए 89 प्रतिशत, चने के लिए 59 प्रतिशत, जौ के लिए 58 प्रतिशत और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बढ़ोतरी से न केवल किसानों को उनकी फसलों का न्यायसंगत मूल्य मिलेगा, बल्कि फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, और किसानों की आय में सुधार होगा। सरकार का यह कदम किसानों के हित में एक बड़ी राहत और आर्थिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

कृषि विश्लेषकों के अनुसार, इस तरह के कदमों से किसानों को खेती में जोखिम कम करने और लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी और भारत में खाद्य सुरक्षा और उत्पादन स्थिरता को सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।

राष्ट्रीय चेतना के पावन अवतार : प्रधानमंत्री मोदी की लेखनी में आरएसएस का शताब्दी गान

भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में कुछ संस्थाएँ ऐसी होती हैं, जो केवल संगठन नहीं रहतीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का स्थायी स्वरूप बन जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गाथा भी ऐसी ही है, जिसकी स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष में प्रवेश के अवसर पर एक लंबा और भावपूर्ण लेख लिखकर संघ की शताब्दी यात्रा को केवल एक संगठन की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और उसके उत्थान की यात्रा बताया।

मोदी ने संघ को "शाश्वत राष्ट्रीय चेतना का पावन अवतार" कहकर उसके वास्तविक स्वरूप को अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत की संस्कृति बार-बार विपत्तियों और चुनौतियों के बीच पुनर्जीवित होकर खड़ी होती है, उसी तरह आरएसएस भी राष्ट्रीय जागरण की उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो हर युग की आवश्यकताओं के अनुसार रूप बदलती रहती है। आज जब स्वयंसेवकों की नई पीढ़ी इस शताब्दी काल में प्रवेश कर रही है, तो यह केवल सौभाग्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है।

प्रधानमंत्री ने संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से परे एक विराट दृष्टि के साथ संघ को खड़ा किया। उनकी सोच थी कि यदि राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो पहले मजबूत चरित्र वाले व्यक्तियों का निर्माण करना होगा। यही कारण था कि उन्होंने ₹शाखा₹ को संघ का आधार बनाया, जहाँ एक स्वयंसेवक अनुशासन, सामूहिकता और सेवा के संस्कार ग्रहण करता है। मोदी ने शाखाओं को ₹चरित्र निर्माण की यज्ञ वेदी₹ कहा, जिसने बीते सौ वर्षों में लाखों युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए गढ़ा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति को भी दोहराया और बताया कि डॉ. हेडगेवार और अनेक स्वयंसेवक सक्रिय रूप से इस महान आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संघ पर आरोप और षड्यंत्रों के कारण कई बार संकट आया, तब भी स्वयंसेवकों ने समाज के प्रति कटुता नहीं रखी। वे हमेशा मानते रहे कि समाज अलग नहीं, बल्कि स्वयं उनका अपना अंग है। यही भावना संघ को सदा ₹राष्ट्र प्रथम₹ की साधना में स्थिर रखती है। मोदी ने अपने लेख में संघ के उन योगदानों का भी स्मरण किया, जिनसे समाज के कमजोर, वंचित और उपेक्षित वर्गों में आत्मगौरव का संचार हुआ। उन्होंने उल्लेख किया कि गुरुजी गोलवलकर, बालासाहेब देवरस, रज्जू भैया और सुदर्शन जैसे प्रमुखों ने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया। वहीं वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत ने ₹एक कुआँ, एक मंदिर और एक श्मशान₹ का संदेश देकर सामाजिक समरसता का व्यावहारिक दृष्टिकोण रखा।

प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि आज की चुनौतियाँ सौ वर्ष पहले की चुनौतियों से भिन्न हैं। भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इस यात्रा में संघ ने समयानुकूल एक नया रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने आरएसएस के ₹पाँच परिवर्तन₹ का उल्लेख किया—आत्म-जागरूकता, सामाजिक समरसता, परिवार जागरण, नागरिक भावना और पर्यावरण संरक्षण। मोदी ने आत्म-जागरूकता को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और स्वदेशी गौरव से जोड़ा, सामाजिक समरसता को सामाजिक न्याय और समान अवसर से, परिवार जागरण को सांस्कृतिक धरोहर से, नागरिक भावना को राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध से और पर्यावरण संरक्षण को भविष्य की पीढ़ियों के जीवन-संतुलन से।

इस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि संघ का सौ वर्ष केवल अतीत की स्मृतियों का पर्व नहीं है, बल्कि यह भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। संघ ने जिस तरह चरित्रवान व्यक्तियों का निर्माण कर राष्ट्र की नींव को मजबूत किया है, उसी तरह आने वाले समय में भी वह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने में योगदान देगा। मोदी की लेखनी में यह केवल आरएसएस का इतिहास नहीं, बल्कि भारत के पुनर्जागरण की वह धारा है जो बीते सौ वर्षों से प्रवाहित हो रही है और आने वाले युगों तक चलती रहेगी।

कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी और परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य नसीम खान ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। खान ने इस संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा और घटना की गंभीरता को रेखांकित किया।

पत्र में नसीम खान ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता प्रिंटो महादेवन ने कथित तौर पर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी, जो कि बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला है। उन्होंने महादेवन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही खान ने जोर देकर कहा कि राहुल

गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी की जान पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

नसीम खान ने पत्र में यह भी लिखा कि राहुल गांधी ने हमेशा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई है और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवार की सुरक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विशेषज्ञों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार, ऐसे खतरे राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए न केवल सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि राजनीतिक दलों और संबंधित अधिकारियों द्वारा कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करना भी जरूरी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से अपेक्षा की जा रही है कि राहुल गांधी और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नेताओं की व्यक्तिगत सुरक्षा दोनों ही सुरक्षित रहें।